बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 101

कठिन है डगर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आगामी बैठक नई अध्यक्ष निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आगामी गुरुवार को होगी। यह परिषद की कुल मिलाकर 35वीं और नई सरकार आने के बाद पहली बैठक होगी। यह बैठक अहम है क्योंकि इसका आयोजन जीएसटी लागू होने के दो वर्ष पूरे होने के महज 10 दिन पहले हो रहा है। इस अवधि में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर कर व्यवस्था में तब्दील हो गई है। हालांकि इसके डिजाइन में कई खामियां हैं और प्रक्रियात्मक दिक्कतें समस्या बनी हुई हैं। कुल मिलाकर राजस्व संग्रह अभी भी अनुमान से कम है। जीएसटी परिषद और उसकी नई अध्यक्ष के समक्ष क्या प्रमुख चुनौतियां हैं?

पहली और सबसे अहम बात यह है कि पिछली बैठकों की तरह जीएसटी परिषद की तरह सलाह मशविरे की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। चूंकि परिषद की पहली बैठक सितंबर 2016 में हुई थी इसलिए पिछले 33 महीनों में इस संस्थान के तमाम निर्णय आपसी सहमति से लिए गए। इस दौरान मतदान का सहारा नहीं लेना पड़ा जबकि कानूनन उसकी व्यवस्था की गई है। आम सहमति के तरीके ने परिषद के संघीय चरित्र को मजबूत किया है और कई छोटे तथा विपक्ष द्वारा शासित राज्यों की उन आशंकाओं को दूर किया है जिनको लग रहा था कि जीएसटी परिषद उनकी चिंताओं की अनदेखी करेगी। सहमति का रास्ता भी बाधाओं से रहित नहीं था। सलाह मशविरे के बल पर उनसे निजात पाना अक्सर समय खपाऊ साबित हुआ है। परंतु इसने संघीय संस्था की मजबूत बुनियाद भी तैयार की है जो वस्तु एवं सेवा कर लगाने के लिए जवाबदेह है। ऐसे में यह महत्त्वपूर्ण है कि नई अध्यक्ष के अधीन जीएसटी परिषद उस भरोसे को कायम रखे।

इसके अलावा यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि परिषद आने वाली अहम चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करे। जैसा कि इसी समाचार पत्र में कहा गया था परिषद की अगली बैठक में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम का प्रस्ताव पेश करने पर विचार होगा। यह मौजूदा व्यवस्था से बेहतर होगा और इससे राजस्व की लीकेज दूर करने में भी मदद मिलेगी। नई व्यवस्था बिना किसी दिक्कत के लागू हो जाए इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। निर्यात की जीरो रेटिंग के लिए सहज व्यवस्था लागू करना भी उतना ही अहम है। फिलहाल निर्यातकों द्वारा चुकता कर को रिफंड करने की प्रक्रिया जटिल और देरी से भरपूर है। इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कमी आती है।

विभिन्न जिंसों और सेवाओं की दरों को तार्किक बनाने का लक्ष्य भी परिषद के लिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। मौजूदा विविध दरों के स्थान पर तीन व्यापक दायरे तय करने होंगे। फिलहाल कुल मिलाकर पांच दर हैं। इसके अलावा कुछ वस्तुओं और सेवाओं का इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग करने से कुछ विसंगतियां उत्पन्न होती हैं जिनको दूर करना होगा। पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन को जीएसटी व्यवस्था के अधीन लाने का दूरगामी लक्ष्य भी लेकर चलना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें जिस हद तक तेल क्षेत्र के राजस्व पर निर्भर हैं उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि इन पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी दर से ऊपर कुछ विशेष शुल्क लगाया जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो उसके पास राजस्व की आवक बनी रहेगी और साथ ही साथ उद्योग जगत को भी ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद पर चुकता कर का कुछ लाभ मिल सकेगा। जीएसटी परिषद की बात करें तो आगे की राह आसान नहीं है लेकिन और अधिक सुधार लागू करने और दरों को तार्किक बनाने के काम में किसी तरह की देरी कतई नहीं होनी चाहिए।

बिनय सिन्हा

भारत के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा

किसी भी देश की सुरक्षा के बहुत से आयाम होते हैं। इनमें से सेना केवल एक आयाम है, लेकिन यह सबसे अहम है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **प्रेमवीर दास**

चुनावी शोर-शराबा थम चुका है और नई सरकार आ गई है। ऐसे में चुनाव के अहम मुद्दों- राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रवाद की अलग-अलग व्याख्या हो सकती है और इसका विश्लेषण करना मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा एक निश्चित शब्दावली है। दो साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उसके बाद इस साल फरवरी में पुलवामा आतंकी हमला हुआ, जिसके तत्काल बाद बालाकोट पर जवाबी हमला किया गया। इस मुद्दे पर चुनाव प्रचार में तगड़ी बयानबाजी देखने को मिली। पाकिस्तान को दुश्मन देश मानते हुए उसे कड़ा सबक सिखाने की बात कही गई।

रोचक बात यह है कि इन बयानों में चीन का कोई जिक्र नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित नियंत्रण रेखा करीब 700 किलोमीटर है, लेकिन चीन के साथ करीब 4,000 किलोमीटर की सीमा को लेकर विवाद है। इतना ही नहीं, चीन अक्साई चीन में हमारी जमीन दबाए बैठा है और अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर थोड़ा अधिक यथार्थवादी नजरिया अपनाना जरूरी है।

किसी भी देश की सुरक्षा के बहुत से आयाम होते हैं। इनमें सैन्य दृष्टिकोण केवल एक आयाम है, लेकिन यह सबसे अहम है। इस नजरिये को ध्यान में रखते हुए हम यहां प्रासंगिक समीकरणों की पड़ताल करते हैं। जमीन पर हमने उत्तरी सीमाओं पर सेनाएं तैनात कर रखी हैं। लेकिन यह मुश्किल से ही कभी देखने को मिला हो कि पाकिस्तान के किसी सैन्य मुख्यालय ने भारत के साथ टकराव का समर्थन किया हो। दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच संतुलन को लेकर भी ऐसा कहा जा सकता है। यह सही है कि पाकिस्तान की वायु सेना ने बालाकोट हमले के अगले ही दिन पलटवार किया था और हमारे एक मिग-21 को गिरा दिया था, लेकिन उसके विमान हमारी सीमा के अंदर नहीं आए थे। नौसेना के लिहाज से हमें बढ़त हासिल है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के हमारी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने की आशंका दूर-दर तक नजर नहीं आती है।

हां, पाकिस्तान की तरफ से भारत में और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अप्रत्यक्ष मदद आगे भी जारी रहने के आसार हैं। हालांकि इस पर पाकिस्तान के खस्ता आर्थिक हालात, अंतरराष्ट्रीय दबाव और भारत की कड़ी कार्रवाई से अंकुश लगेगा। समुद्री रास्ते से आतंकी वारदात का खतरा बरकरार है। इस रास्ते का इस्तेमाल वर्ष 2008 में मुंबई हमले या 1993 के बम धमाकों में किया गया। 1993 के बम धमाकों में समुद्री रास्ते से विस्फोटक लाए गए थे और इन्हें रत्नागिरि तट पर उतारा गया था। असली चिंता घाटी को लेकर है। सीधे कहें तो आतंकवाद से राजनीतिक या अन्य किसी अन्य तरीके से निपटना होगा, लेकिन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सैन्य चुनौती देने की पाकिस्तान में क्षमता नहीं है।

चीन की स्थिति बहुत अलग है। सीमा पर किसी टकराव में चीन को निर्णायक बढ़त हासिल है। वायु क्षेत्र में दोनों की स्थिति लगभग समान है क्योंकि चीनी विमानों को ऊंचाई से उड़ान भरनी पड़ेगी, जिससे उनकी क्षमता में कुछ कमी आएगी। लेकिन फिर भी यह कहना आशावादी होगा कि हम उसके बराबर हैं। इस समय हमें हिंद महासागर क्षेत्र में निश्चित रूप से स्पष्ट बढ़त हासिल है। लेकिन यह बढ़त तेजी से कम हो रही है क्योंकि विश्व के इस हिस्से में चीन की नौसेना की मौजूदगी बढ़ रही है। चीन की ग्वादर और जिबूती के नौसैन्य अड्डों तक पहुंच है। चीन के क्षेत्रीय दावों से टकराव पैदा होने के आसार हैं। यह डोकलाम में भी देखने को मिला है और बीते वर्षों में अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही है और वह एशियाई और वैश्विक भूराजनीति में बड़ा कद हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में यह तय है कि उसे चीन के प्रत्यक्ष और परोक्ष टकराव का सामना करना पड़ेगा, जिसमें चीन के पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध महज एक पहलू हैं।

व्यापार आगे भी एकतरफा बना रहेगा और दक्षिण चीन सागर में हमारे ऊपर दबाव बढ़ सकता है। दक्षिणी चीन सागर के जरिये हमारा आधे से अधिक व्यापार होता है। इस वजह से भारत के लिए चीन पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है। चीन हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं में इसे प्रमुखता दी जानी चाहिए।

यह तर्क दिया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत-चीन संबंधों में कुछ सुधार आया है। डोकलाम पर कुछ समय तनाव रहा, लेकिन अब यह मुद्दा खत्म हो गया है। दोनों देशों के प्रमुखों की वुहान में मुलाकात उम्मीद से अधिक सौहार्दपूर्ण रही। हाल में चीन ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का भी समर्थन किया है, जिसे सकारात्मक माना जा सकता है। चीन को व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका के भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह हमारे साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।

इसके बावजूद चीन ताकत में अमेरिका से मुकाबला करने में हमेशा भारत को दूसरी तरफ पाता है, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए दोनों देशों के बीच मतभेद बने रहेंगे, जो समय की भूराजनीतिक जरूरतों के आधार पर 'संभाले या बढ़ाए' जा सकते हैं। हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। यह तय है कि चीन और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ मित्रता आगे भी बनी रहेगी।

कुल मिलाकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं पाकिस्तान की तुलना में चीन पर ज्यादा केंद्रित होनी चाहिए। पाकिस्तान से मिलने वाली संभावित चुनौतियां चीन की तुलना में बहुत कम हैं, इसलिए हमारी सैन्य तैयारी इसी के मुताबिक की जानी चाहिए। नौसेना हमारी ताकत है और इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। वहीं अन्य क्षेत्रों में कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए। सीमाओं पर अपर्याप्त सड़क संपर्क का अभाव दूर किया जाना चाहिए, जो थल सेना की जल्द तैनाती में बाधा बनता है। इन मुद्दों और सेना के ढांचे को समग्र रूप में देखा जाना चाहिए।

अच्छी बात यह है कि हमें नए विदेश मंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति मिले हैं, जो विदेशी मामलों की पेचीदगियों को बहुत बेहतर समझते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का पद पर बने रहना अच्छा है, लेकिन उन्हें नए कदमों से बचना चाहिए। चुनाव हो चुके हैं, इसलिए नई सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा पर फिर से विचार करना चाहिए।

(लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे हैं।)

सरकार के समक्ष राजस्व के मोर्चे पर क्या हैं चुनौतियां

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

अप्रैल 2019 के सीजीए के आंकड़े वित्त मंत्रालय के समक्ष मौजूदा राजस्व चुनौतियों को भी रेखांकित करते हैं। मंत्रालय की टीम फिलहाल 2019-20 का बजट तैयार करने में लगी हुई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय को अगले वर्ष पर टाल कर कितना व्यय संकुचन हासिल किया गया? या फिर इसका कितना हिस्सा बजट से इतर सरकारी कंपनियों द्वारा लिए गए व्यय का परिणाम था?

केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के अपने संशोधित व्यय अनुमान में करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये की कटौती की। इस राशि में से करीब 13,000 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत व्यय में कम की गई जबकि शेष 1.32 लाख करोड़ रुपये की राशि राजस्व व्यय के अधीन।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, व्यय को सीमित करने का अधिकांश काम बजट से इतर उधारी के माध्यम से किया गया। ऐसे ऋण का बोझ सरकारी क्षेत्र की कई कंपनियों पर पड़ा। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय आवास बैंक और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इसका उदाहरण हैं।

हालांकि ऐसी उधारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है परंतु महा लेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सच बयान करते हैं। उदाहरण के लिए सीजीए के वर्ष 2018-19 के आंकड़े बताते हैं कि कैसे खाद्य सब्सिडी बिल संशोधित अनुमान में 40 फीसदी घटकर 1.71 लाख करोड़ रुपये हो गया।

खाद्य सब्सिडी में आई कमी कुल राजस्व व्यय संकुचन के तकरीबन आधे के बराबर है। यानी पूरा बोझ एफसीआई पर डाल दिया गया। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अप्रैल 2019 के आंकड़ों में इस स्थगित व्यय का कोई प्रभाव नजर नहीं आता।

अप्रैल 2019 में सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिए 46,862 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जो इससे पिछले वर्ष की समान अवधि की 48,430 करोड़ रुपये से कम थी। दो वर्ष के बजट अनुमान के आधार पर भी सरकार का खाद्य व्यय बिल 2019 में 25 फीसदी के कम स्तर पर था। 2018 में यह 29 फीसदी रहा था। स्पष्ट है कि यहां लंबित व्यय का कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय ये आंकड़े बहुत सीमित संकुचन दर्शाते हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वयं को खाद्य सब्सिडी के किसी भी तरह के व्यय से पूरी तरह मुक्त है। अब ऋण का बोझ एफसीआई पर है। यह अलग विषय है कि इसका एफसीआई की वित्तीय सेहत पर क्या असर होगा? हालांकि देश के सार्वजनिक वित्त क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके विपरीत उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर सरकार का सब्सिडी व्यय अप्रैल 2019 में जमकर बढ़ा। अप्रैल 2018 में जहां पेट्रोलियम पर 2,582 करोड़ रुपये और उर्वरक पर 7,124 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी, वहीं इस वर्ष अप्रैल में यह बढ़कर क्रमशः 5,281 करोड़ और 16,943 करोड़ रुपये हो गई। यह अपने आप में पहेली है। 2018-19 में पेट्रोलियम और उर्वरक के लिए सीजीए के अंतिम आंकड़े में संशोधित आंकड़ों की तुलना में कोई बड़ी कमी नहीं की गई। इसके बावजूद अप्रैल 2019 का व्यय अहम उछाल दर्शाता है।

बहरहाल, यह स्पष्ट है कि खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरक जैसे प्रमुख सब्सिडी बिल 2019-20 में चिंता का विषय नहीं होंगे। बिना स्थगित व्यय के 2.96 लाख करोड़ रुपये के प्रमुख सब्सिडी बिल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बशर्ते कि कच्चे तेल की कीमत 65-70 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में बनी रहे।

अप्रैल 2019 के सीजीए के आंकड़े वित्त मंत्रालय के समक्ष मौजूदा राजस्व चुनौतियों को भी रेखांकित करते हैं। मंत्रालय की टीम फिलहाल 2019-20 का बजट तैयार करने में लगी हुई है। उसने यह ध्यान दिया होगा कि अप्रैल 2019 का कुल कर राजस्व 71,637 करोड़ रुपये अनुमानित था। यह 2018 के समान महीने के 57,533 करोड़ रुपये से 24.5 फीसदी अधिक है। राजस्व वृद्धि का स्तर सामान्य परिस्थितियों में उत्साहवर्धक है लेकिन वास्तविक राजस्व संग्रह में कमी के कारण यह हमें बताता है कि आगे कितनी अहम चुनौतियां व्याप्त हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए विशुद्ध कर राजस्व वृद्धि का लक्ष्य 29.5 फीसदी है। क्या अगले वर्ष इसे और बढ़ाया जा सकता है? या फिर बजट निर्माता चुनौतियों की पहचान करेंगे और लक्ष्यों को हकीकत के और अधिक करीब रखने का प्रयास करेंगे?

राजस्व मोर्चे पर गैर ऋण पूंजी प्राप्ति इकलौता ऐसा तरीका है जो कुछ राहत दिलाता है। सरकार ने अप्रैल 2019 में 2,350 करोड़ रुपये का राजस्व विनिवेश से हासिल किया। इसमें से 476 करोड़ रुपये की राशि रेल विकास निगम लिमिटेड में 12 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर कर आईपीओ से जुटाई गई थी। जबकि 1,874 करोड़ रुपये की राशि शत्रु संपत्ति की बिक्री से आई थी। यह राशि अप्रैल 2018 में दर्ज 435 करोड़ रुपये की राशि से काफी अधिक थी। हालांकि सरकार अप्रैल 2019 में चुनाव की तैयारी में लगी रही होगी लेकिन ऐसा लगता है कि कर राजस्व और विनिवेश के मोर्चे पर प्रदर्शन बेहतर रहा। इससे वर्ष 2018-19 के समान माह की तुलना में बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे के स्तर में कमी आई। अब जबकि नई सरकार आगामी 5 जुलाई को अपना पहला बजट प्रस्तुत करने जा रही है तो शायद इन दो क्षेत्रों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

कानाफूसी

विश्वसनीय विकल्प

हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अब पार्टी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रही है। अपनी केंद्रीय समिति की बैठक में माकपा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने वाम दलों के साथ गठबंधन नहीं करके गलती की है। इसका फायदा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला क्योंकि उसके समर्थक वाम और कांग्रेस दोनों को ही ममता बनर्जी का विश्वसनीय विकल्प नहीं मान रहे थे। माकपा को उम्मीद है कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई कारणों की पड़ताल करके आगामी विधानसभा चुनाव में उसके साथ हाथ मिलाएगी। ये चुनाव 2021 की पहली छमाही में होने हैं। उधर माकपा और कांग्रेस में कई लोग यह भी मान रहे हैं कि ममता के नेतृत्व वाली सरकार को गिराकर केंद्र जल्दी चुनाव करा सकता है।

गृह जिले में राहत

मध्य प्रदेश में किसी भी समय बिजली का गुल हो जाना आम बात है। यह बात प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उम्मीद के मुताबिक ही आरोप प्रत्यारोप का खेल चालू हो गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जहां बिजली आपूर्ति में हो रही बाधा के लिए भाजपाई मानसिकता वाले कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं भाजपा ने सरकार को नाकाम करार देना शुरू कर दिया है। परंतु अच्छी खबर मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा के लिए है। बीते मंगलवार को जहां जबलपुर और सिवनी जिलों में एक घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही, वहीं छिंदवाड़ा में केवल 38 सेकंड के लिए बिजली गई। कमलनाथ आठ बार छिंदवाड़ा से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जगह बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से सांसद बने हैं। राज्य की प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 19,000 मेगावॉट है जबकि गर्मियों में औसत खपत रोजना 9,500 मेगावॉट है।

आपका पक्ष

एनपीए वसूली में नए दिशानिर्देश

रिजर्व बैंक ने वर्षों से गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की समस्या से जूझ रहे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए जो नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं उससे यह उम्मीद बनती है कि बैंकों के ऋण शीघ्र वापस होंगे। बैंकों का तेजी से बढ़ता एनपीए वित्तीय क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार एनपीए का आंकड़ा 10 लाख करोड़ के ऊपर ही रहा है। जाहिर है कि बैंकों की यह रकम कर्जदारों के बीच फंसी हुई है जिसे बैंक वसूल पाने में नाकाम रहे हैं। अधिकतर बैंकों की माली हालत संतोषजनक नहीं है। पिछले साल कुछ बैंक कर्ज देने की स्थिति में नहीं थे। बैंकों को इस स्थिति में लाने में बड़े कारोबारियों की मुख्य भूमिका रही है। बैंकिंग क्षेत्र की बिगड़ती हालत से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। रिजर्व बैंक ने अब एनपीए की वसूली के लिए जो नए दिशानिर्देश जारी किए हैं इससे कर्जदारों को भी कुछ राहत मिल सकेगी। अब बैंकों को डिफॉल्टर की पहचान के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। अब बैंक खुद ही तय करेंगे कि किस डिफॉल्टर के साथ क्या करना है। वास्तव में इस नियम का मकसद यही है कि कर्जदार को जरा समय दिया जाए ताकि वसूली का रास्ता बंद नहीं हो। अधिकतर मामले कानूनी जाल में फंस जाते हैं और कर्ज वसूली की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। कर्जदारों का बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मामले को कानूनी जाल में उलझाकर उसका फायदा उठाता है और लंबे समय तक मामले को लटकाए रखना चाहता है। एनपीए ऐसे ही कर्जदारों से बढ़ा है। एनपीए के बढ़ते बोझ से चिंतित रिजर्व बैंक ने पिछले साल बैंकों पर सख्ती की थी और एनपीए वसूली के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए थे। किसी भी राष्ट्र के विकास में बैंकों का अहम योगदान होता है। इसलिए बैंकों को सुदृढ़ बनाना और आवश्यक हो जाता है।

दुर्गेश शर्मा, गोरखपुर

रिजर्व बैंक ने एनपीए की समस्या से जूझ रहे बैंकों को नए दिशानिर्देश दिए हैं

स्वरोजगार के लिए उठाएं कदम

देश में रोजगार के लिए तात्कालिक के साथ दूरगामी नीतियां बना कर लागू करना होगा। रोजगार की समस्या का समाधान बढ़ती जनसंख्या के आधार पर निकालना होगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को करीब आठ माह बीत गए हैं। महात्मा गांधी ने हर हाथ को रोजगार देने के लिए चरखा अपनाने का सुझाव दिया था। वर्तमान समय के अनुसार हस्तकरघा और कौशल का कक्षा पांच से समावेश करना होगा। पांचवीं कक्षा से ही बच्चों को हस्तकला में निपुण करना होगा। इस नीति से छोटे बजट में करोड़ों हाथ रोजगार से जुड़ जाएंगे। माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजने लगेंगे। इससे पढ़ाई के साथ धन उपार्जन हो सकेगा। इसकी सफलता के लिए शिक्षा नीति में सिर्फ मातृभाषा और आठवीं अनुसूची की कोई एक भाषा का प्रावधान करना होगा। अंग्रेजी के कारण समय, शक्ति और धन का अनावश्यक बोझ बालकों पर पड़ता है। इससे गांव तथा शहर के कमजोर आर्थिक स्थिति वाला परिवार का हर बच्चा स्वावलंबी बन सकेगा। शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान बना देने से देश को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। शिक्षा नीति में अगर राष्ट्रीयता, चरित्र और नैतिकता को जोड़ दिया जाए तो यह देश में हिंसा, अपराध और चरित्रहीनता से मुक्त कर सकेगा।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

काजू का न्यूनतम आयात मूल्य बढ़ा

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 13 जून

भारत सरकार ने काजू गिरी के न्यूनतम आयात मूल्य में बड़ा इजाफा किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के अनुसार टूटे काजू का न्यूनतम आयात मूल्य 288 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 680 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इसी प्रकार साबुत काजू का आयात मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 720 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि इस मूल्य से कम पर काजू आयात वर्जित है। घरेलू स्तर पर उगाए जाने वाले काजू को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया गया है।

केरल काजू उद्योग संयुक्त परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि यह परेशानी से जूझ रहे केरल के काजू उद्योग के लिए सकारात्मक कदम है। इससे घरेलू स्तर पर उत्पादित काजू की अधिक मांग का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे छोटे स्तर के प्रसंस्करण केंद्रों को मदद मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए और रोजगार सृजित होगा। परिषद ने सरकार से केरल में काजू उद्योग को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। देश में तकरीबन 3.5 लाख टन काजू गिरी का उत्पादन होता है।

महाराष्ट्र में गन्ने की बुआई पर पड़ा सूखे का असर

सूखे से चीनी उत्पादन पर असर

रॉयटर्स
मुंबई, 13 जून

पिछले साल के मुकाबले वर्ष 2019-20 में देश के चीनी उत्पादन में 15 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है क्योंकि गंभीर सूखे से प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन को नुकसान पहुंचा है। उद्योग के सूत्रों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी। इस गिरावट से भारतीय चीनी मिलों पर अतिरिक्त चीनी निर्यात करने का दबाव कम होगा। इससे वैश्विक दामों को मदद मिलने की संभावना है। देश से खेप भेजने में मिलने वाली छूट की वजह से ये दाम पिछले साल 20 प्रतिशत से ज्यादा गिर गए थे।

नैशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि अक्टूबर से शुरू होने वाले फसल वर्ष 2019-20 में दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक का उत्पादन 2.8 से 2.9 करोड़ टन रह सकता है जो इस वर्ष के 3.3 करोड़ टन उत्पादन से कम है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सूखे के कारण गन्ने के बुआई क्षेत्र में काफी गिरावट आई है। पानी की कमी से भी गन्ने की पैदावार प्रभावित हो सकती है।

करोड़ों भारतीय देरी से आ रहे मॉनसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि उन्हें लू के बीच पीने के पानी को सुरक्षित रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। यह लू तेजी से जलाशयों को सूखा रही है और देश भर का तापमान बढ़ा रही है।

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन

- **2019-20** में उत्पादन **2.8** से **2.9** करोड़ टन के बीच रहने की संभावना इस वर्ष **3.3** करोड़ टन रहा
- महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन **65** लाख टन रहा, पिछले साल था **1.07** करोड़ टन
- वर्ष **2018-19** के लिए **50** लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है

महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ का अनुमान है कि 2019-20 के फसल वर्ष में कटाई किए जाने वाले गन्ने का रकबा पिछले साल की तुलना में 28 प्रतिशत कम हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले सीजन में देश के दूसरे सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र का उत्पादन 65 लाख टन रह सकता है जो मौजूदा फसल वर्ष से 39.2 प्रतिशत कम है। गायकवाड़ ने कहा कि अगर इस साल राज्य में कम बारिश होती है तो यह गिरावट और ज्यादा हो सकती है।

मौसम विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि आम तौर पर मॉनसून महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में 10 जून तक पहुंचता है लेकिन इस साल यह अभी तक नहीं आया है। चूंकि पानी किल्लत से कुछ क्षेत्रों में पशुओं के चारे की कमी पैदा हो गई है इसलिए महाराष्ट्र के रामदास पवार जैसे किसान चारे के लिए गन्ना बेच रहे हैं। उन्होंने कहा, 'गन्ना मुर्झा रहा था। मैंने दो एकड़ में कटाई की और चारे के रूप में गन्ना मवेशियों के एक शिविर को बेच दिया।'

गन्ने की जोरदार उपज वाले वर्षों और रिकॉर्ड चीनी उत्पादन ने चीनी के घरेलू दामों को नुकसान पहुंचाया है जिससे मिलों के लिए किसानों का बकाया भुगतान करने में मुश्किल हो गई। गन्ना बकाया और बढ़ता स्टॉक कम करने के लिए केंद्र सरकार मिलों को विदेशों को चीनी बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। नाइकनवरे ने कहा कि दो साल की प्रचुर उपज के कारण पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होने की वजह से कम उत्पादन के बावजूद भारत को अब भी अगले सीजन में चीनी निर्यात करना पड़ेगा।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने पिछले महीने कहा था कि 1 अक्टूबर को नए सीजन की शुरुआत में चीनी का स्टॉक बढ़कर 1.47 करोड़ टन होने के आसार हैं जो पिछले साल के मुकाबले 37.4 प्रतिशत ज्यादा है। एक वैश्विक कंपनी के मुंबई स्थित व्यापारी ने कहा कि निर्यात के बिना स्टॉक का स्तर कम नहीं होगा। सरकार अगले साल भी निर्यात प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।

लौह अयस्क वितरण में विविधीकरण से बंद होगी खींचतान !

अदिति दिवेकर
मुंबई, 13 जून

घरेलू लौह अयस्क व्यापारी खनिकों और इस्पात उद्योग के बीच चल रही रस्साकशी से निपटने के लिए रेटिंग एजेंसियां संसाधन वितरण में विविधीकरण को प्रमुख समाधान के रूप में देख रही हैं। हाल ही में इस्पात निर्माताओं ने सरकार से मार्च 2020 में समाप्त होने पर लौह अयस्क खनन लाइसेंसों की नीलामी करने की माग की है। फिलहाल ये लाइसेंस निजी खनिकों के पास हैं। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएसआईएमए) और पैलेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएआई) ने खदान नीलामी पर जोर देते हुए योजना निर्माण करने वाले थिंक टैंक नीति आयोग को पत्र लिखा है। दूसरी ओर भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (फिमी) ने अलग से नीति आयोग से व्यापारी खदानों की पट्टे की वैधता 2030 तक बढ़ाने की अपील की है। इससे इस क्षेत्र के दो वर्गों के बीच चल रही रस्साकशी और बढ़ गई है।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर (कॉरपोरेट्स) महावीर जैन ने बताया कि इसके पीछे विचार यह है कि घरेलू बाजार में लागत प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ कच्चे माल का मुक्त प्रवाह हो जिससे इस्पात उत्पादन की लागत और फिर समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिले। इस वजह से नीलामी में निजी उपभोग वाली खदानों के साथ-साथ गैर निजी उपभोग वाली खदानों का मिश्रण रहना चाहिए।

उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि कुल लगभग 8-8.5 करोड़ टन लौह अयस्क वाले खनन पट्टे मार्च 2020 में समाप्त होने हैं। इसमें से लगभग 6.5 करोड़ टन अयस्क अकेले ओडिशा में हैं। इसके अलावा इनमें से अधिकांश खदानें आहुजा, रूंगटा माइंस और केजेएस अहलूवालिया समूह जैसे निजी व्यापारी खनिकों के पास हैं। ये निजी व्यापारी खनिक इंडक्शन फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इकाइयों को अयस्क की आपूर्ति करते हैं जो मुख्य रूप से देश के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। अधिकारियों ने कहा कि जब नीलामी की शुरुआत हो तो इस संबंध में अंतर होना चाहिए कि उद्योग के कौन-से वर्ग (व्यापारी या निजी उपभोग वाले खनिक) को किस प्रकार की खदान के लिए बोली लगानी चाहिए। क्रिसिल रिसर्च की निदेशक हेतल गांधी ने कहा कि बढ़ते स्टॉक के बावजूद कई व्यापारी खदानें ऐसी जगहों पर एक-दूसरे से जुड़ गई हैं या उनके पट्टे लिए गए हैं जहां पहले ही बड़ा स्टॉक है। इससे नए बोलीदाता को दुविधा होगी।

इस्पात उद्योग

किसी मौजूदा खनन कंपनी के पास केवल खदान संबंधी संसाधन ही नहीं बल्कि ट्रकों, घाटों, परियोजना स्थलों पर कार्यालयों, क्रेनों और पट्टे पर लिए अन्य उपकरणों के रूप में अपना बुनियादी ढांचा रहता है। इसके अलावा एजेंसियों का कहना है कि अगर नीलाम की जाने वाली खदानों का सीमांकन नहीं किया जाता है तो निजी व्यापारिक खनिकों के मुकाबले निजी उपभोग करने वाले भागीदार निश्चित तौर पर मजबूत स्थिति में होंगे क्योंकि निजी व्यापारिक खनिक उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते। गांधी ने बताया कि अगर निजी उपभोग वाले इस्पात निर्माताओं के लिए नीलामी को खुला रखा जाता है तो बोली का प्रीमियम अधिक हो जाएगा जैसा कि निजी उपभोग की पिछले साल की नीलामी में नजर आया था। इससे व्यापारी खनिकों को नुकसान हो सकता है। केयर रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादकों में शामिल है। वित्त वर्ष 19 में इसका कुल उत्पादन 9.5 प्रतिशत बढ़कर करीब 22 करोड़ टन हो गया है। मार्च 2020 में कुछ लौह अयस्क खदानों की लाइसेंस अवधि खत्म होने वाली है इसलिए खनिकों से उम्मीद है कि वे अपने उत्पादन में तेजी लाएंगे और स्टॉक बढ़ाएंगे। वित्त वर्ष 2020 में उत्पादन वृद्धि वित्त वर्ष 2019 के अनुरूप रहने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on June 13	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,753.5	-6.4	2,014.0	-6.0
Copper	5,828.5	-10.7	6,603.0	-3.9
Nickel	11,745.0	-9.3	12,587.4	-7.9
Lead	1,918.0	-8.9	2,186.6	-2.5
Tin	19,325.0	-9.1	20,571.5	-14.3
Zinc	2,640.5	-8.3	2,992.2	-6.7
Gold ($/ounce)	1,334.6*	1.9	1,461.1	1.3
Silver ($/ounce)	14.8*	-4.3	16.4	-4.6
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	63.1*	-6.1	60.5	-9.6
Natural Gas ($/mmBtu)	2.4*	-16.0	2.4	-14.8
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	187.9	-11.2	280.5	5.8
Maize	199.7*	3.7	261.5	7.5
Sugar	335.7*	-1.1	486.5	3.4
Palm oil	505.0	-2.9	815.2	-6.3
Rubber	2,161.7*	32.8	2,229.8	22.1
Coffee Robusta	1,404.0*	-6.4	2,165.0	15.4
Cotton	1,462.5	-12.4	1,817.7	1.5

* As on Jun 13, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 69.5& 1 0unce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	104.0	79983
Oil and Oilseeds	153.4	62054
Spices	0.3	30
Metal (Jun 12)		
Metal- non ferrous	7031.5	99987
Metal- precious	6337.6	1070
Oil and gas(Jun 12)		
Gas	701.0	14580
Oil	11793.2	2243

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	206.9	88412
Grains	266.8	151200
Oil and Oilseeds	746.3	604240
Others	116.7	64310
Pulses	208.3	196310
Spices	170.3	63152

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Mentha Oil (Jun 28)	1345.3	2.0
Crude Palm Oil (Jun 28)	499.9	1.3
Cotton (Jun 28)	21480.0	1.0
Gold Guinea (Jun 28)	26087.0	0.4
Aluminium (Jun 28)	143.4	0.3
Aluminium Mini (Jun 28)	143.6	0.3
Losers (* % Change)		
Crude Oil (Jun 19)	3596.0	-3.3
Crude Oil Mumbai (Jun 19)	3598.0	-3.3
Lead Mini (Jun 28)	154.6	-0.9
Lead (Jun 28)	154.7	-0.9
Copper (Jun 28)	407.4	-0.7
COPPERM (Jun 28)	407.4	-0.7

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Soyabean Indore (Jun 20)	3702.0	1.4
GuarGum 5T-Jodhpur (Jun 20)	8573.0	1.4
Guar Seed 10 (Jun 20)	4240.0	1.4
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1134.5	1.2
CottonSeed Oil-Akola (Jun 20)	2758.5	1.1
Maize-Gulabbagh (Jun 20)	1818.0	1.0
Chana-Bikaner (Jun 20)	4445.0	0.9
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jun 20)	755.6	0.8
Mustard Seed Rape Oil (Jun 20)	3930.0	0.5
Losers (* % Change)		
Jeera Unjha (Jun 20)	17565.0	-1.7
Turmeric Nizamabad (Jun 20)	6728.0	-1.1
CastorSeed New-Disa (Jun 20)	5408.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Jun 14)	2791.0	3.0
Alumini-Mumbai (Jun 28)	143.6	1.8
Aluminium Mum (Jun 28)	143.4	1.7
Lead Mum (Jun 28)	154.7	1.3
Crude Oil Mum* (Jun 19)	3596.0	1.3
Lead Min Mumbai (Jun 28)	154.6	1.2
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jun 28)	1345.3	-5.8
Cotton-Rajkot (Jun 28)	21480.0	-2.5
Gold Petal-Mumbai (Jun 28)	3256.0	-0.6
Nickel Mumbai (Jun 28)	866.5	-0.5
Zinc Mini Mumbai (Jun 28)	206.1	-0.1
Zinc Mumbai (Jun 28)	206.3	0.0

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Jun 20)	6728.0	2.9
Jeera Unjha (Jun 20)	17565.0	0.7
Maize-Sangli (Jun 20)	2299.0	0.3
29 mm Cotton-Rajkot (Jun 20)	21840.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Jun 20)	6986.0	-7.3
Soy Bean Indore (Jun 20)	3702.0	-2.6
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jun 20)	8573.0	-1.5
Crude Palm Oil Kandl (Jun 28)	489.3	-0.9
Barley Jaipur (Jun 20)	1825.0	-0.6

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals .....Mumbai

Aluminium utensil scrap /kg	120.....(121)
Aluminium ingots /kg	140.....(143)
Brass sheet cutting /kg	340.....(340)
Brass utensil scraps/kg	320.....(320)
Copper heavy scrap /kg	427.....(428)
Copper utensil scraps/kg	403.....(403)
Copper wire bar /kg	459.....(461)
Lead ingots /kg	152.....(152)
Nickel Cathodes /kg	875.....(870)
Tin slabs /kg	1430.....(1420)
Zinc slabs /kg	208.....(209)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton .....Mumbai

Bengal Deshi /Qtl	11614.....(11614)
DCH - 32 /Qtl	15325.....(15325)
Jaydhar /Qtl	10995.....(10995)
Shankar- 6 /Qtl	12851.....(12823)

Source:Cotton Association of India

Oil .....Mumbai

Castor FSG /10kg	1140.....(1140)
Castor Comm /10kg	1130.....(1130)
Ricebran oil/10kg	740.....(740)
Groundnut oil /10kg	1030.....(1020)
Linseed oil /10kg	815.....(815)
Karanji /10kg	710.....(710)
Palm oil /10kg	577.....(580)
Sunflower exp ref /10kg	770.....(770)
Sunflower oil exp /10kg	735.....(735)
Soyabean ref / 10kg	765.....(742)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar .....Mumbai

Mumbai M-30 /Qtl	3252-3242.....(3252-3382)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel .....

NYSE Crude	52.6.....(51.14)
Brent Crude (UK)	62.98.....(60.66)
Brent Crude (WTI)	51.14.....(51.14)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.36.....(2.39)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	378.45.....(367.76)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	37900.....(37900)
Furnace Oil spot/ K.L.	36950.....(36950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold .....Mumbai

Standard (99.50 Purity) /10 gms	32655.....(32582)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	32786.....(32713)
Silver.999/ kg	36750.....(36675)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX & NCDEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	21804.55	21815.70
Alumini-Mumbai (M)	1 K	141.80	141.05
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2075.00	2000.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	1837.65	1836.20
Brass-Jamnagar (M)	1 KG	325.00	325.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	5449.40	5480.95
Castor Seed-Kadi (N)	X	5410.00	5517.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4351.80	4351.80
Chana Delhi (N)	1 Q	4522.50	4539.05
Chana-Akola (N)	X	4425.00	4550.00
Copper Mumbai (M)*	1 K	408.85	406.10
Coriander-Gondal (N)	X	7169.00	7169.00
Coriander-Jaipur (N)	X	7212.50	7152.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7537.05	7537.10
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2800.00	2829.55
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2906.55	2950.00
Cotton-Kadi (N)	1 B	21751.95	21991.00
CPO-Kandla (M)	10 K	499.20	502.30
Crude Oil Mum (M)*	1 BL	3698.00	3549.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	487.95	493.55
Degummed Soy oil-KDL (N)	X	717.25	717.25
Gold Ahm (M)	10 G	32590.00	32632.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	26177.00	26211.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3269.00	3276.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	8612.50	8700.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4280.30	4325.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1238.75	1233.20
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17650.00	17600.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	17476.20	17440.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1236.70	1244.70
Kapas-Rajkot (N)	X	1237.20	1240.00
Lead Mum (M)	1 K	153.75	152.65
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2075.00	2080.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	1720.15	1725.05
Maize-Erode (N)	X	2308.90	2318.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	1950.00	1870.00
Maize-Sangli (N)	X	2295.00	2292.85
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4076.50	4089.40
Natural Gas Hazira (M)*	1 MB	166.50	165.60
Nickel Mumbai (M)	1 K	859.60	871.10
Pepper-Kochi (N)	1 Q	36861.55	36975.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1850.00	1851.10
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	565.00	566.65
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	754.05	759.75
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	741.85	740.15
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	751.00	754.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	15500.00	15500.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	36629.00	36720.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	3771.00	3802.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3743.75	3825.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	3770.00	3787.50
Soy Bean-Akola (N)	X	3691.00	3700.00
Soymeal Indore (N)	1 T	31238.00	31413.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3295.00	3280.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3384.80	3386.40
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3150.00	3165.35
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3476.20	3466.65
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3288.40	3282.85
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3111.25	3117.50
Tin Mumbai (M)*	1 K	1343.75	1339.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6552.50	6536.95
Wheat Delhi (N)	1 Q	2017.50	2016.65
Wheat Kota (N)	1 Q	1950.00	1956.55
Wheat New Indore (N)	1 Q	1900.00	1900.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	1910.00	1910.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	1987.50	1987.50
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4733.40	4733.15
Zinc Mumbai (M)	1 K	207.70	206.30

* as on Jun 12, 19

(M) MCX Spot & (N) NCDEX Spot prices

जिंस वायदा

बेस मेट्ल्स वायदा कांट्रैक्ट्स
हेजर्स के लिए मूल्य का निर्माण
MCX
METAL & ENERGY
Trade with Trust

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (गुरुवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jun 28	21450, 21540, 21330, 21480	5047	764	46990
Jul 31	21570, 21680, 21460, 21600	2037	327	26849
Aug 30	21600, 21620, 21480, 21580	1148	129	5655
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jun 20	2750, 2809, 2746, 2758.5	230	17	880
Jul 19	2794, 2861.5, 2785, 2842	57170	3676	61410
Aug 20	2841.5, 2900, 2828, 2884.5	9190	781	15430
Sep 20	2841, 2900, 2833, 2885	1830	170	5360
Dec 20	2154.5, 2187, 2154.5, 2182.5	920	86	2800
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1134, 1137.5, 1126, 1134.5	508	369	2532
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Jun 20	1825, 1825, 1825, 1825	200	4	990
Jul 19	1834, 1834, 1830, 1830	30	3	3100
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jun 20	4229, 4249, 4229, 4240	930	25	2630
Jul 19	4240, 4287, 4232, 4266	55560	3826	116640
Aug 20	4265, 4349.5, 4265, 4328.5	5240	332	25210
Maize-Gulabbagh NCDEX(1 Qtl)				
Jun 20	1840, 1840, 1817, 1818	300	13	760
Jul 19	1851, 1866, 1850, 1856	1220	49	1840
Aug 20	1900, 1900, 1900, 1900	10	1	10
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jun 20	5450, 5452, 5400, 5408	3655	330	7805
Jul 19	5494, 5526, 5424, 5490	54565	4698	234335
Aug 20	5582, 5604, 5502, 5566	14185	885	23800
Sep 20	5624, 5624, 5624, 5624	5	1	180
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jun 28	496.9, 500.3, 494.1, 499.9	10160	712	40390
Jul 31	500.6, 503.8, 496.9, 502.5	5670	383	20170
Aug 30	501.3, 506.5, 499.9, 504.9	1660	92	1180
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jun 28	1325, 1353.7, 1323.1, 1345.3	399.24	951	204.84
Jul 31	1334, 1362.2, 1332.5, 1354.8	92.88	228	103.68
Aug 30	1350, 1355, 1350, 1352.5	0.72	2	5.04
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jun 20	3930, 3935, 3915, 3930	600	18	10380
Jul 19	3928, 3941, 3920, 3935	14260	1084	105530
Aug 20	3957, 3970, 3951, 3960	1300	114	6750
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jun 20	751.5, 756.1, 750.1, 755.55	5240	300	13890
Jul 19	735, 738, 733.9, 737.95	12300	838	51100
Aug 20	721, 724, 720, 723.05	3930	240	15740
Sep 20	712, 712.9, 711, 711.6	680	57	2560
Oct 18	707, 707, 707, 707	10	1	10
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jun 20	3700, 3705, 3695, 3702	650	35	1160
Jul 19	3665, 3710, 3660, 3694	26290	1993	110000
Aug 20	3700, 3726, 3686, 3714	5710	447	20230
Sep 20	3700, 3731, 3700, 3713	200	14	320
Oct 18	3520, 3520, 3485, 3485	60	4	450
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jun 20	8560, 8600, 8560, 8573	865	71	1250
Jul 19	8589, 8668, 8569, 8633	11315	1608	58420
Aug 20	8749, 8789, 8700, 8762	1335	169	4570
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jun 20	4459, 4460, 4420, 4445	2590	59	3360
Jul 19	4440, 4468, 4413, 4425	38460	2419	148910
Aug 20	4470, 4504, 4453, 4468	5360	327	35700
Sep 20	4510, 4531, 4510, 4523	290	26	250
Wheat-Kota NCDEX(1 Qtl)				
Jun 20	1950, 1950, 1950, 1950	10	1	400
Jul 19	1978, 1978, 1975, 1977	330	19	7600
Aug 20	1999, 1999, 1999, 1999	20	2	60
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jun 14	2791, 2791, 2791, 2791	0.1	1	1
Jul 15	2385, 2410, 2385, 2395	0.3	3	6.4
Aug 14	1960, 1998, 1960, 1976.2	0.6	6	18
Sep 13	1717, 1730, 1717, 1723.5	0.4	4	4.1
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jun 20	-, 6986, -, 6986	10	1	840
Jul 19	7062, 7089, 7000, 7013	5040	429	29610
Aug 20	7177, 7180, 7100, 7145	330	28	2200
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jun 20	17755, 17800, 17530, 17565	339	58	1179
Jul 19	17750, 17800, 17350, 17415	5058	1295	6324
Aug 20	17840, 17875, 17480, 17510	795	241	684
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Jun 20	6748, 6748, 6712, 6728	130	21	800
Jul 19	6786, 6820, 6662, 6680	2575	471	15940
Aug 20	7058, 7058, 6902, 6930	785	133	5480
Sep 20	7130, 7130, 7050, 7050	15	3	95
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Jun 28	143, 143.55, 142.6, 143.4	10300	1670	11260
Jul 31	144.75, 145.25, 144, 145	850	149	3750
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jun 28	143.2, 143.65, 142.8, 143.45	3210	2506	4